Shelving of Central Sector Projects

2804. VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are considering shelving of those central projects in the core sector which have crossed 60 per cent of their gestation period and have consumed 5 per cent of their project cost;

(b) if so, the names of such projects and the amount already spent on them;

(c) whether Government would fix responsibility for the tardy progress in completion of these projects; and

(d) the steps taken or proposed to be taken to ensure that other ongoing projects or future projects do not fall in the above category?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) Yes sir.

(b) No decision has been taken so far.

(c) Does not arise, in view of (b) above.

(c) Measures generally taken to improve the pace of implementation are given in Statement.

Statement

Steps taken by the Government to Streamline for Preparing the Original Estimates and Implementation of Projects

(i) Two-stage project approval for facilitating adequate preparation, environmental and other clearances and infrastructure planning at stage I before a project is finally approved for implementation at stage II.

(ii) Proper monitoring of projects at regular intervals, at various levels to identify constraints and take remedial measures

(iii) Indepth review of the progress by the project authorities and Administrative Ministries.

(iv) Setting up of Task Force/ Empowered Committees for speedy finalsation of contract packages, solving land acquisition and other problems.

(v) Close follow up by the concerned administrative Ministries and project authorities with the State Government, equipment suppliers, contractors, consultants and other concerned agencies to minimise delays.

(vi) Inter-ministerial coordination.

Rural Population Below the Poverty Line

2805. PROF. RAM KAPSE: Will the Minsiter of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of a NCA & R Survey which reveals that 39% of the rural population is living below the poverty line; if so, the details thereof;

(b) whether Planning Commission had claimed about a year ago that the population living below the poverty line was 19%;

(c) if so, the reasons for the anomaly figures quoted by the Planning Commission; and

(d) whether correct estimate of the actual poverty percentage is not available with the Planning Commission; if so, how the viability of various development schemes launched by Government can be justified?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF THE STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) A study on Human Development Profile of India conducted by NCAER based on a survey on

household income has estimated the percentage of people below the poverty line in rural areas of 16 States as 39 per cent in 1994.

(b) Based on the methodology outlined in the report of the Task Force on Projection of Minimum Needs and Effective Consumption Demand (1979), the incidence of poverty in the country was estimated as 18.96 per cent in 1993-94 based on the data of Sub Sample-I of National Sample Survey on Consumer Expenditure, 50th Round.

(c) The differences in the two estimates are due to the methodology adopted and the data base.

(d) The Planning Commission estimates the incidence of povety using the quinquennial National Sample Survey data on Consumer Expenditure. The incidence of poverty in 1993-94 is estimated as 35.97 per cent following the recently adopted official methodology which is based on the report of the Expert Group on Estimation of Proportion and Number of Poor.

अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति से संबद्व बेरोजगार युवकों के निर्धारण हेतु समिति गठित करना

2806.**श्री रामजीलाल**:

श्री अजीत जोगी:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से संबद्व बेरोजगार युवकों की संख्या के मूल्यांकन हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां,तो ऐसे युवकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और यदि उपर्युक्त भाग"क" का उत्तर नहीं हो तो क्या ऐसा आकलन किया जाएगा;और

सरकार दवारा उन युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु क्या नई कार्यवाही और पहल की गई हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) से (ग) अनु.जाति/अनुजनजाति के बेरोजगार युवाओं को संख्या के मूल्यांकन हेतु कोई समिति गठन नहीं की गई है और इस समय ऐसी कोई समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है । बहरहाल,मौजूदा गरीबी उन्मूलन स्कीमों के लाभ,जो रोजगार मुहैया कराती है,अनु.जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित सभी ही प्राप्त हो रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराने वाली प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है,एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम,जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम/जनसंख्या के कमजोर वर्गो का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करने के लिए इन गरीबी उम्मूलन कार्यक्रमों में विशेष एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। आईआरडीपी के अन्तर्गत इस बात पर विचार किया जा रहा है कि कवर किए गए लाभ ग्राहियों में से 50%अनु.जातियों तथा अनु.जनजातियों से संबंधित होने चाहिए । जेआरवाई तथा इएएस के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्ति लक्षित समूह में आते हैं,जिसमें से अनुसूचित जातियों,अनु.जनजातियों तथा मुक्त बन्धुआ मजदूरों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है । शहरी विकास सेक्टर में दो शहरी गरीबी उम्मूलन स्कीमें चल रही हैं ये है: नेहरू रोजगार योजना एंव प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम/प्रधानमंत्री की रोजगार योजना केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जा रही है ताकि ग्रामीण तथा शहरी,दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें । पीएमआरवाई के अन्तर्गत,अनु.जाति/अनु.जनजाति लाभग्राहियों के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान है । कल्याण मंत्रालय आदिवासी क्षेत्रो में व्यावसासिक प्रशिक्षण संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित करता है,जो आदिवासी युवाओं को रोजगार/ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराता हैं ।

केन्द्रीय योजनाओं में विलंब होना

2807. **श्री नागमणि**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विलंबित केंद्रीय योजनाओं की संख्या बढ़ रही हैं;